पानी की कमी दूर करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स

Bhupender.Sharma@timesgroup.com

नई दिल्ली : पानी की कमी को देखते हुए शहरों के लिए पानी का रीयूज करना जरूरी बन गया है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत अब शहरों से निकलने वाले इस्तेमाल किए जा चुके पानी को महत्व दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि शहरों में उपयोग में लाए जा चुके पानी को विभिन्न कामों के लिए एकत्रित, रीसाइकल और रीयूज किया जा सके। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत छोटे शहरों में 4,900 एमएलडी क्षमता वाले ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 11,785 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इससे छोटे शहरों में जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहर के सीवेज या इस्तेमाल हो चुके पानी को जलाशयों में न छोड़कर पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। घरों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले पानी को ट्रीट किया जाए और उसके बाद ही जलाशयों में छोड़ा जाए।

इंदौर, चंडीगढ़ जैसे शहर दिखा रहे राह : केंद्रीय आवास मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव जैन बताते हैं कि शहरों में जल प्रबंधन को लेकर किए जा रहे उपायों से कई शहर अब वॉटर प्लस प्रमाणित शहरों की श्रेणी में हैं, जो दूसरे शहरों को इस्तेमाल किए हुए पानी का तेजी से प्रबंधन करने की राह दिखा रहे हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), इंदौर, सूरत, तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसुरु सभी वॉटर प्लस प्रमाणित शहर हैं। ये शहर न केवल उपयोग किए गए पानी को इकट्ठा करने और सुरक्षित रूप से ट्रीट करने में सक्षम हैं, बल्कि ट्रीट किए गए पानी को रीयूज भी किया जा रहा है।

nwda.gov.in